बिहार में गांव से अधिक शहरों में गरीबी बड़ी चुनौती

डेवलपिंग अरबन इकोनॉमी ऑफ बिहार पर सेमिनार

पटना के होटल मौर्य में शुक्रवार को डेवलपिंग अरबन इकोनॉमी ऑफ बिहार विषय पर आयोजित सेमिनार में देश के जाने-माने विशेषज्ञों ने शिरकत की. उन्होंने कहा कि शहरों के विकास के लिए बिहार के खास संदर्भ व परिस्थितियों के मुताबिक नीति बनाने की जरूरत है. शहरों को सुव्यवस्थित करना होगा, संरचना निर्माण के लिए नीति बनानी होगी और शहरों की मार्केटिंग करनी होगी.

सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते आइपीइ संस्था के ग्लोबल डायरेक्टर डॉ गंगाधर झा (बायें). नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ (दायें) व राष्ट्रीय सेमिनार में मौजूद लोग (बीच में).

संवाददाता ■ पटना

चीन के शंघाई शहर की आबादी उस देश की 1.2 फीसदी है, जबकि उसका जीडीपी में योगदान 21 फीसदी है. इसी तरह अफ्रीका में छह बड़े शहर हैं. वहां 34 फीसदी जनसंख्या रहती है, जबकि उन शहरों का जीडीपी में 58 फीसदी योगदान है. आइपीइ संस्था के ग्लोबल डायरेक्टर डॉ गंगाधर झा ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि शहरों के विकास के लिए संरचना की आवश्यकता है. संरचना बेहतर होगी, तभी लोग निवेश करने को तैयार होंगे. आर्थिक विकास में नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

नगरकर्मियों की है कमी

श्री झा 'डेवलपिंग अरबन इकोनॉमी ऑफ बिहार' पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के पहले तकनीकी सत्र को संबोधित कर रहे थे. इसका विषय था- 'शहरों के स्थायी आर्थिक विकास में संस्थागत अवसर व चुनौतियां.' उन्होंने कहा, एक समय था जब राजतंत्र हुआ, फिर प्रजातंत्र की नींव पड़ी. अब समय आ गया है, जब विकास के लिए सरकार, निजी क्षेत्र व बिजनेस हाउस को इंगेज किया जा रहा है. ये सभी मिल कर विकास की मुहिम चला सकते हैं. अगर किसी शहर में संरचना है, तो उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत है. बिहार में नगर प्रशासन का निदेशालय नहीं है. नगरकर्मी की कमी है. बिहार की स्थिति विचित्र है. यहां गांव से अधिक गरीब शहरों में रहते हैं. सरकार की प्राथमिकता में शहरी विकास नहीं है. 2007 में जो नगरपालिका अधिनियम बना, उसका नगरपालिकाओं की संरचना से कोई तालमेल नहीं है. अभी राज्य में शहरीकरण होना है. यह अच्छा अवसर है कि संरचना निर्माण को लेकर बेहतर नीति तैयार कर ली जाये, तो जब भी शहरीकरण होगा, इसका लाभ मिलेगा. संस्थागत विकास के लिए राज्य, क्षेत्रीय व स्थानीय स्तर पर संरचना तैयार की जानी चाहिए. शहरों के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र भरती नियमावली तैयार होनी चाहिए.

बिहार की तरफ देख रहा पूरा देश : वैद्य

नेशनल अरबन इंस्टीट्यूट ऑफ अफेयर (एनआइयूए) के निदेशक चेतन वैद्य ने कहा कि बिहार की तरफ पूरा देश देख रहा है. आज जो बिहार कर रहा है, बाद में दूसरे लोग उसे अपना रहे हैं. यहां के शहरों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं. उन्होंने बताया कि गुजरात का बारदोली शहर है. वह अपने साथ सूरत सहित आस पास के तीन-चार जिलों के अलावा महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों का आर्थिक केंद्र बन गया है. यह है शहरीकरण व आर्थिक विकास का मॉडल. हर शहर के स्थानीय आर्थिक गतिविधियों की पहचान होनी चाहिए. शहरीकरण से आर्थिक आय का सीधा संबंध है. शहरों के आर्थिक विकास में नगर निकायों की भूमिका संविधान की 12वीं अनुसूची में स्पष्ट कर दी गयी है. जो भी सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाये गये, वे ठीक से नहीं बने है. अब कोशिश होनी चाहिए कि सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम-दो बनाते समय उसके साथ बिजनेस प्लान भी तैयार किया जाये.

हर शहर का भी हो नेता : रवींद्रा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ ए रवींद्रा ने बताया कि नगरों के विकास के लिए उस शहर का भी नेता होना आवश्यक है. जैसे बिहार के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसी तरह पटना शहर का भी अपना नेता होना चाहिए. शहर में भी राजनीतिक कार्यपाल की जरूरत है. बिना स्थानीय नेता तैयार किये शहर का विकास संभव नहीं है. डा राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई राजनेता नगर निकायों में भी चुने गये. शहरों का सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाना है. आखिर यह प्लान कौन बनायेगा. स्थानीय निकाय की क्षमता कम है. शहरों को प्रतिस्पद्धी बनाना है. इसके लिए वहां की बुनियादी संरचना आवश्यक है. सड़क, पानी व पावर की जरूरत है. उद्योग जगत किसी शहर को किस रूप में देखता है. उन्होंने कहा कि लोक-निजी साझेदारी (पीपीपी) का काम बहुत आगे बढ़ चुका है. आश्चर्य है कि पीपीपी को लेकर स्पष्टता नहीं है. इसके लिए नीति बनाने की जरूरत है.

सुविधा होगी, तो उद्योग आयेंगे : दीपक

बियाडा के प्रबंध निदेशक दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जहां पर सुविधा होगी, वहां उद्योगपति भी आयेंगे. अगर किसी को उद्योग लगाना हो और कंपनी के बड़े अधिकारियों को ठहरने के लिए अच्छे होटल न हो, तो भी कोई आने से परहेज करेगा. पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, बरौनी, पूर्णिया व औरंगाबाद में उद्योग आ रहे हैं.

सरकार नहीं करती हस्तक्षेप: डॉ सिद्धार्थ

नगर विकास विभाग के सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि नगर निकायों में होनेवाले टकराव को लेकर सरकार दिशा निर्देश देती है. सरकार स्थानीय निकायों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती. वे मेयर और नगर आयुक्तों के बीच आये दिन होनेवाले टकराव को लेकर पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे.

पहले सत्र की अध्यक्षता भारत सरकार के सलाहकार आनंद मोहन ने की.

jetScreenshot